

JKCL/CS/BSE-35/NSE-472020-21/

Dated: 04/09/2020

The Bombay Stock Exchange Ltd., Corporate Relationship Department, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001 Scrip Code:532644 (ISIN.INE 823G01014) Through BSE Listing Centre	National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051 Scrip Code: JKCEMENT (ISIN.INE823G01014) Through : NEAPS
---	---

Subject: Newspaper Insertion about despatch of Postal Ballot Notice on 31.8.20

In terms of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, please find enclosed herewith the newspaper insertion about despatch of Postal Ballot Notice on 31.8.20, published on Tuesday, September 1, 2020 in the following newspapers:

- 1. Business Standard (English), All Editions**
- 2. Business Standard (Hindi), All Editions**
- 3. Hindustan (Hindi), Kanpur Edition**

This is for your information and records.

Thanking you

Yours faithfully,
For J.K.Cement Ltd



Shambhu Singh)

Asst.Vice President (Legal)
Company Secretary & Compliance officer
M.No.FCS-5836

Encls: As Above

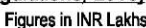


UNITS:

J. K. Cement Works, Nimbahera
J. K. Cement Works, Mangrol
J. K. Cement Works, Gotan
J. K. Cement Works, Muddapur
J. K. Cement Works, Aligarh

J. K. Cement Works, Jharli
J. K. White Cement Works, Gotan
J. K. White, Katni
J. K. Power, Bamania
J. K. Cement Works, Balasinor



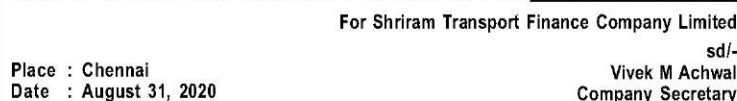
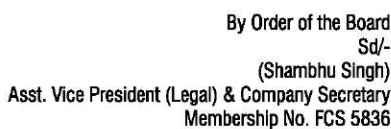


Notes:

- 1.The above audited financial results have been approved by the audit committee and board of directors in their meeting held on August 29, 2020.
- 2.The above is an extract of the detailed format of annual audited financial statement for year ending 31st March, 2020 accompanied by independent Auditor report filed with the stock exchange under Regulation 52 of SEBI(LORD) Regulations, 2015. The full financials is available on the website of Bombay Stock Exchange (BSE).
- 3.The financial statements have been prepared in accordance with INS AD notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.
- 4.Management has exercised necessary due diligence to ensure that the said comparative results provide a true and fair view of its affairs.

Place: Lucknow
Date: August 29, 2020

Rahul J. Mitta
Managing Director & CEO
DIN: 01873793



स्कूल-कॉलेज नहीं खुलेंगे, साप्ताहिक बंदी जारी

अनलाक-4 की गाइड लाइन

कानपुर। प्रदेश सरकार के बाद डीएम आलोक तिवारी ने भी अनलाक-4 की गाइड लाइन जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। इसके बाहर अनलाक-4 में कैंद और राज्य सरकार द्वारा दी गई सहूलितें प्रभावी रहेगी। यह आदेश मंगलवार से प्रभावी हो जाएगा। डीएम ने भी साफ कर दिया है कि 30 सितंबर तक किसी स्कूल-कॉलेज बंद रहेगी। शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक लागू साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी।

- ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा के लिए अनुमति जारी रहेगी और इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। 21 सितंबर के बाद स्कूलों में 50 फीसदी शिक्षकों और स्टॉफ को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बुलाया जा सकेगा। इसके लिए स्टैडर्ड ऑफ आपरेंटिंग (एसओपी) परिवार कल्याण मंत्रालय जारी करेगा।
- कंटेनमेंट जोन के बाहर कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी अपने शिक्षकों से मार्ग निर्देशन के लिए स्वीच्छक आधार पर जा सकेंगे। इसके लिए माता-पिता की लिखित अनुमति होनी चाहिए। यह व्यवस्था 21 सितंबर से लागू होगी। इसकी भी एसओपी अलग से जारी की जाएगी।
- केंद्र या राज्य सरकार के राष्ट्रीय कोशल प्रशिक्षण संस्थानों, आईटीआई, कोशल

- विकास मिशन में प्रशिक्षण की अनुमति होगी। उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान को भी 21 सितंबर के बाद ट्रेनिंग की मंजूरी दी गई है।
- पीपवर्षी शोधार्थियों, तकनीकी, व्यवसायिक प्रोग्रामों, जिनमें प्रयोगशाला की जरूरत हो संबंधित पीजी छात्रों को अनुमति होगी। मूल्यांकन के संबंध में उच्च शिक्षा-शिक्षक विभाग, गृह मंत्रालय के मध्य विचार विमर्श के उपरांत होगा।
- 21 सितंबर के बाद समस्त सामाजिक, आधुनिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति होगी। अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सेनेटाइजर लाना होगा।

- 20 सितंबर तक शादी विवाह समारोह में अधिकतम 30 और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों की अनुमति होगी। 21 सितंबर के बाद 100 लोग शामिल हो सकेंगे।
- मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार बंद रहेंगे। 21 सितंबर के बाद ओपन एयर थियेटर शुरू करने की अनुमति होगी।
- कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लागू रहेगा
- कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी गतिविधियों की ही अनुमति होगी।
- कंटेनमेंट जोन क्षेत्र डीएम नोटीफाइड करेंगे और केंद्र तथा राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन कराएंगे
- अंतरजनपदीय परिवहन में किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा

बुजुर्गों, बच्चों को निकलने की इजाजत नहीं
65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, कई बीमारियों से पीड़ित, गर्भवती स्त्रियां, दस वर्ष आयु तक के बच्चों को निकलने की इजाजत नहीं होगी। विशेष परिस्थितियों में निकलने की छूट होगी

शुक्रवार रात 10 से सोमवार सुबह 5 बजे तक बंदी जारी
प्रत्येक सोमवार रातों 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कुछ प्रतिबंधों के साथ 14 जुलाई से लागू व्यवस्था जारी रहेगी।

6जोड़ी ट्रेनों सेंट्रल से गुजर सकतीं

कानपुर। अनलाक के दौरान रेलवे ने तीसरे चरण में कुछ और ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। लोड का आकलन करने के बाद स्थानीय रेल प्रशासन ने छह जोड़ी और ट्रेनों को चलाने का प्रस्ताव बोर्ड की भेज दिया है। इनके चलाने पर 7 सितंबर के बाद मंथन होगा और दूसरे सप्ताह तक ये ट्रेनें चल सकती हैं। पता हो कि रेलवे ने पहले चरण में छह राजधानी तो दूसरे चरण में 160 ट्रेनों को चलाने का फैसला किया था।

ये रही छह जोड़ी ट्रेनें

- लखनऊ-एलटीटी फुल्ली एसी
- कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस
- स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस
- कानपुर-जम्मूती एक्सप्रेस
- इंदौर झ पटना एक्सप्रेस
- प्रयागराज-जयपुर एक्सप्रेस

साढ़े तीन घंटे बंद रही हैलट कार्डियोलॉजी की बिजली

कानपुर | प्रमुख संवाददाता

मेट्रो के चल रहे कार्य की वजह से हैलट फीडर का शटडाउन दिन में 10.30 से 2 बजे तक लिया गया। इसकी वजह से हैलट अस्पताल, कार्डियोलॉजी, जेके केसर अस्पताल सहित कई कालोनियों की बिजली गुल रही। गर्मी और उमस से मरीजों-तीमारदारों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसके साथ 11 सबस्टेशनों में फाल्ट और शटडाउन से कोई ढाई लाख की आबादी परेशान रही। कहीं पर पानी का संकट तो कहीं पर लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई।

की सप्लाई को नई एचटी लाइन के पोल लगाने को दिन में 11.30 से शाम 5 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रही। एच ब्लाक सबस्टेशन के जंगली देवी व एनएलसी फीडर की मेन लाइन पर पेड़ गिरा। इसकी वजह से दिन में 11 से 2 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहने से कोई 40 हजार की आबादी परेशान रही। इसी तरह बसंत मरीजों-तीमारदारों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसके साथ लाइन बदलने को शटडाउन लिया गया। इस कारण इलाके में 12 से 3 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रही। इसी तरह रिंग रोड के एमईएस फीडर की लाइन पर पेड़ की एक डाल गिरी तो तार टूट गया। तार बदलने को दो से चार बजे तक इलाके की बिजली गुल रही।



यूरोपीय संघ बैंक कानपुर मेट्रो में अरबों रुपए का करेगा निवेश



कानपुर/नई दिल्ली | हिंदी

यूरोपीय संघ के बाहर अपने दूसरे सबसे बड़े ऑपरेशन में यूरोपियन संघ बैंक कानपुर शहर की मेट्रो रेल परियोजना में 650 मिलियन यूरो (करीब 57,07,46,67,214 रुपये) का निवेश करेगा। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) 18 एलिवेटेड और 12 भूमगत स्टेशनों के

वित्तीय मामले में ऐसे बढ़ेगी कानपुर मेट्रो

- 5551.99 करोड़ का लोन (निवेश) ईआईबी करेगा
 - 4656.25 करोड़ रुपए केंद्र और राज्य लाएंगे
 - 1967.33 करोड़ रुपए केंद्र द्वारा मुहैया कराए जाएंगे
 - 2688.62 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा मिलेंगे
 - 671.08 करोड़ के टेक्स की प्रतिपूर्ति राज्य करेगा
 - 197.46 करोड़ से ऑटो फेयर कलेक्शन सिस्टम
- कानपुर स्थानीय निकायों से ये होगी मदद**
- 200 करोड़ उग्र. आवास विकास प्रश्न से मिलेंगे
 - 100 करोड़ कानपुर विकास प्राधिकरण को देने होंगे
 - 50 करोड़ यूपीसीडा (यूपीएसआईसीसी) से मिलेंगे

ये है परियोजना की लागत

- 11076 करोड़ कुल परियोजना की लागत
- 2300 करोड़ रुपए है पहले फेज के निर्माण की लागत
- 734.56 करोड़ के टेंडर स्वीकृत हैं पहले फेज में

साथ 32.4 किलोमीटर मेट्रो लाइन बैंक का भारत में कनेक्टिविटी का वित्त पोषण करेगा। यूरोपीय संघ परियोजनाएं और हरित ढांचा

परियोजना के लिए अब कुल निवेश 2.6 बिलियन यूरो का है। यूरोपीय संघ बैंक का भारत में हरित बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में यह पांचवां निवेश है। ये उत्तर प्रदेश राज्य में दूसरा निवेश है। कानपुर निवेश के साथ, भारत में मेट्रो रेल प्रणालियों के लिए ईआईबी की अनुमोदित सहायता की कुल राशि 2.65 बिलियन यूरो तक पहुंच गई है, जो भारत में पूरे ईआईबी निवेश पोर्टफोलियो के आधे से अधिक है। ईयू बैंक ने भोपाल में मेट्रो रेल सिस्टम, पुणे, बेंगलूर और लखनऊ में निवेश किया है।

मेट्रो परियोजना के लिए कम नहीं पड़ेगी रकम

कानपुर | प्रमुख संवाददाता

अब कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए रकम की कमी नहीं होगी। यूरोपियन इनवेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) के साथ अनुबंध होने के साथ ही वित्तीय संकट समाप्त हो गया है। यूपीएमआरसी के एमडी कुमार केशव ने कहा है कि विकास कार्यों की रफ्तार और तेज होगी।

इस परियोजना के लिए जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइट्स ने तैयार की थी उसी आधार पर ईआईबी से निवेश हुआ है। ईआईबी की टीम ने मेट्रो के दोनों रूट का वर्ष 2015 में ही सर्वे कर लिया था। यूपीएमआरसी के एमडी कहते हैं कि पहले चरण का काम दिसंबर 2021 तक पूरा करने की कोशिश है।

राज्य सरकार 1,332 करोड़ खर्च करेगी

कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की लागत करीब 16,975 करोड़ है। इसमें राज्य सरकार 1,332 करोड़ खर्च करेगी। आवास विकास परिषद को 200 करोड़, कानपुर विकास प्राधिकरण को 100 करोड़ खर्च करना है जबकि यूपीसीडा 50 करोड़ रुपये लाएगा। अगर मेट्रो प्रोजेक्ट पर करीब 12,901 करोड़ का खर्च आएगा। इसमें 1,009 करोड़ रुपये राज्य सरकार लाएगी। आवास विकास परिषद को 117 करोड़ रुपये, अगर विकास प्राधिकरण को 57 व यूपीसीडा को 26 करोड़ रुपये तीन साल में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए अपने अंशदान के रूप में देने हैं।

माल बुकिंग की भी जानकारी 139 पर

कानपुर। रेलवे ने माल और पार्सल की बुकिंग कराने की हर जानकारी के लिए अखिल भारतीय एकल संपर्क हेल्पलाइन सेवा 139 शुरू कर दी है। इस टोल फ्री नंबर पर व्यापारी-उद्यमी फोन करके माल और पार्सल बुकिंग की हर जानकारी ले सकेंगे।

मंगलवार (1 सितंबर-2020) से सेवा शुरू हो जाएगी। एनईआर के इज्जतनगर मंडल के पीआरओ राजेंद्र सिंह ने बताया कि दिन में 10 से 6 बजे के बीच फोन करने वालों को तत्काल सीधी जानकारी मिलेगी और इसके बाद यानी कि शाम 6.01 से सुबह 9.59 बजे तक कोई फोन करता तो उसका फोन रजिस्टर्ड होगा और तीन घंटे के भीतर कॉल बैंक करके उसे जानकारी दी जाएगी।

लेदर निर्यातकों को राहत देने के लिए नई स्कीम की तैयारी

कानपुर | प्रमुख संवाददाता

तमाम चुनौतियों से जूझती लेदर इंडस्ट्री को राहत देने के लिए नई स्कीम लाने की तैयारी हो रही है। इस संबंध में चर्म निर्यात परिषद (सीएलई) ने कानपुर के लेदर उद्यमियों से डाटा मांगा है। सोमवार को चेन्नई स्थित सीएलई के मुख्यालय से कानपुर के निर्यातकों ने बात की। उन्हें बताया गया कि एमईआईएस की स्कीम दिसंबर में बंद हो रही है और उसके स्थान पर नई स्कीम लाई जा रही है।

इसके लिए कारोबारियों से पूछा गया है कि आप कितनी लेवी, टैक्स और ड्यूटी देते हैं जो जीएसटी में कवर नहीं होता। इसी टैक्स को रिफंड दिखाकर

राहत दी जाएगी। कार्टासिल फार लेदर एक्सपोर्ट के जरिए पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार होगी और उसे सरकार को भेजा जाएगा।

आयात निर्यात एक्सपर्ट जफर फिरोज ने बताया कि एमईआईएस स्कीम ने लेदर इंडस्ट्री की काफी मदद की है लेकिन विषय व्यापार संगठन के दखल के बाद इसे बंद कर दूसरे रास्ते से निर्यातकों की मदद की योजना बन रही है। वेबिनार में सूरि शूज, मॉडल टेनर्स, सुपर टेनरी, एकेएस ग्लोबल, इंडिया ब्रिटिल, गोमोर इंटरनेशनल, ओमेगा इंटरनेशनल, रहमान इंडस्ट्री, नाज एक्सपोर्ट्स और लॉर्ड शिवा इंटरनेशनल आदि कंपनियों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर
संस्थान निर्माण विभाग, मण्डल-2

ई-निविदा सूचना संख्या चं.नि.वि.मण्डल-2/2020/547
आवृत्ति अनिवार्य, संस्था निर्माण विभाग, संस्थान के संयोजक बसुल की ओर से है। (1. नि.सं. 09/सि/निविदा/मण्डल-2/2020-21/01), कार्य का नाम- कनेक्टिविटी सिस्टम के नीचे इट्ट कालेज (FMS-22-034 के रूप में) की छत पर वायर फ्रेमिंग के कार्य हेतु, अनुमानित लागत- ₹. 10,09,560/-, धरोहर राशि- ₹. 20,191/-, कार्य पूर्ण करने की अवधि- 04 माह, (2. नि.सं. 09/सि/निविदा/मण्डल-2/2020-21/02), कार्य का नाम- रिक्त मकान संख्या 392 में सेंटिंग राइट के कार्य हेतु, अनुमानित लागत- ₹. 5,59,764/-, धरोहर राशि- ₹. 1,196/-, कार्य पूर्ण करने की अवधि- 03 माह, (3. नि.सं. 09/सि/निविदा/मण्डल-2/2020-21/03), कार्य का नाम- रिक्त मकान संख्या 314 में सेंटिंग राइट के कार्य हेतु, अनुमानित लागत- ₹. 6,39,438/-, धरोहर राशि- ₹. 12,789/-, कार्य पूर्ण करने की अवधि- 03 माह, (4. नि.सं. 09/सि/निविदा/मण्डल-2/2020-21/04), कार्य का नाम- कनेक्टिविटी सिस्टम के नीचे इट्ट कालेज के 2माह पहले से सेंटिंग तथा सिंथेसिस के प्लास्टर के कार्य हेतु, अनुमानित लागत- ₹. 6,78,039/-, धरोहर राशि- ₹. 11,561/-, कार्य पूर्ण करने की अवधि- 04 माह, योग्य स्थिति के उम्मीदवारों से जो सीबीडब्ल्यू, सीएसएनएल, एमईएस, यूपीसीडब्ल्यू, केन्द्र सरकार के उद्देश्य में उचित क्रेमी में संयोजित हैं से ऑनलाइन प्रस्तावित कर के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं, निविदा सूचना वेबसाइट www.bids.ac.in/india/central.htm पर उपलब्ध है, तथा निविदाएं वेबसाइट www.tenderslive24.com/IT द्वारा ही डाकूनी जाएंगी। निविदाएं दिनांक 10.09.2020 को 15:30 बजे तक प्राप्त की जायेंगी। यदि इस निविदा सूचना के संबंध में कोई भी सुनिश्चय जारी किया जायेगा, जो केवल उपरोक्त वेबसाइट पर ही उपलब्ध होगा।

अधीक्षण अभियन्ता

बुढ़वा मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं

प्रत्येक मंगलवार
मोतीचूर लड्डू ₹120/- किलो
देसी घी के मोतीचूर लड्डू ₹200/- किलो
पेड़ा ₹260/- किलो

Saturday & Sunday Open for Home Delivery
गुरूनादक डिग्री कालेज के सामने लाजपत नगर, कानपुर
Mob.: 9335309729, 7619995553

कानपुर विकास प्राधिकरण

वाहन स्टैण्ड की नीलामी सूचना

कानपुर विकास प्राधिकरण मुख्य कार्यालय भवन, परिसर स्थित स्टैण्ड की नीलामी दिनांक 22.09.2020 अथवा अतिरिक्त अवकाश के दूसरे दिन अपराह्न 3:00 बजे प्रारम्भ होगा परिसर स्थित अटल बिहारी प्रसाद गृह (आडिओरियम हाल) में रिजर्व प्राइज धनांक रुपये 8,50,054.00 पर आहुत की जानी है, नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति वित्त नियंत्रक कानपुर विकास प्राधिकरण के नाम बंधक धनराशि रुपये 25,000.00 का एफ.डी.आर./बैंक ड्राफ्ट धनराशि करण कोष में जमा कर उक्त दिनांक व समय पर नीलामी में भाग ले सकते हैं। उच्चतम बोली दाता द्वारा उच्चतम बोली की 1/4 धनराशि नीलामी स्वीकृत के 24 घण्टे व अवशेष 3/4 धनराशि एक सप्ताह के अन्दर एक मुश्त प्रतिकरण कोष में जमा करना अनिवार्य होगा, जमानती धनराशि अनुबन्ध समाप्ति के उपरान्त ही वापस होगी। शासन द्वारा निर्धारित समस्त टैक्सों का उत्तरदायित्व उच्चतम बोली दाता का ही होगा, नीलामी के नियम व शर्त कार्यालय कार्य दिवस के हेयर टेकर अनुभाग में देखे/प्राप्त किये जा सकते हैं। उच्चतम बोली को स्वीकृति/अस्वीकृति उपाध्यक्ष, का.वि.प्रा. में निहित होगा, जो सर्वमान्य होगा।

मुकेश अग्रवाल
अधीशापी अभियन्ता

By Order of the Board
Sd/-
(Shambhu Singh)
Date: 31st August, 2020
Asst. Vice President (Legal) & Company Secretary
Membership No. FCS 5836

48 करोड़ रुपए से बचे पांच नाले भी होंगे टैप, गंगा में नहीं गिरेगी गंदगी

राहतभरी खबर

कानपुर | प्रमुख संवाददाता

सीसमऊ नाले की तरह ही बचे 5 नाले भी गंगा की तरफ से मोड़ दिए जाएंगे। पाँपिंग स्टेशनों के जरिए इन नालों का सीवेज जाजमऊ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाया जाएगा। वहां सिंचाई के लायक पानी तैयार करके खेतों में भेजा जाएगा। इस योजना पर 48 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

जल निगम की डिटेल्ड प्रोजेक्ट पर रिपोर्ट पर शासन ने अपनी संस्तुति दे दी है और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को भेज दिया है। यह काम नमाफ

शासन ने इस प्रोजेक्ट को एनएमसीजी को भेज दिया है। अब वहां से बजट आवंटित होगा तो इसका काम चालू होगा। फिलहाल हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है।

- ज्ञानेंद्र चौधरी, परियोजनाप्रबंधक (गंगा प्रदूषण नियंत्रण यूनित)

सका था। इनका अभी तक बॉयरोमैडियल ट्रीटमेंट किया जा रहा है जो न तो स्थायी है और न ही अब उतना कारगर रह गया है। अब ये नाले स्थायी तौर पर टैप कर दिए जाएंगे। इसी तरह रानी घाट और रामेश्वर घाट पर भी गंगा तरफ सीवेज न जाने देने के लिए अस्थाई इंतजाम किया गया था। अब इनकी भी टैपिंग हो जाएगी।

डोपीआर में 1.5 किलोमीटर की पाइप डालकर पाँपिंग स्टेशनों के जरिए सीवेज को राइजिंग मेन में डाल दिया जाएगा जो पहले से बनी हुई है। इससे पूरा सीवेज जाजमऊ पहुंचने लगेगा। पांच नालों की टैपिंग के साथ ही 4 पाँपिंग स्टेशन बनाए जाने की योजना है।

ALL NEW
हिन्दुस्तान स्मार्ट
लोकल और वाकल

कानपुर से जुड़ी ताजा खबरों के लिए लॉगऑन करें
smart.livehindustan.com